दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरुवार 11 नवंबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-04, अंक- 44

महत्वपूर्ण एवं खास

बस-टैंकर की टक्कर में जले 12 लोग जिंदा

जोधपुर (आरएनएस)। राजस्थान के जोधपुर-बाड़मेर हाइवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक बस और टैंकर ट्रेलर की टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में सवार 12 लोगों की मौत हो गई है। आशंका है कि इनकी मौत जलकर हुई है। इस बस में 25 लोग सवार थे। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने 10 लोगों को बचा लिया है। इस हादसे के बाद बाड़मेर-जोधपुर हाइवे पर लंबा जाम लग गया है।

कुंडली बॉर्डर पर एक और पंजाब के किसान की मौत, फंदे पर लटका मिला शव

सोनीपत ,10 नवंबर (आरएनएस)। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। धरना दे रहे किसानों की मौत की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच सोनीपल के कुंडली बॉर्डर पर एक और किसान की मौत की खबर सामने आई हैं। बुधवार को प्रदर्शन में शामिल एक किसान का शव फंदे पर लटका मिला। मृतक किसान का पहचान गुरप्रीत सिंह (45) पुत्र गुरमेल सिंह निवासी गांव रुड़की, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक वह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के अमलोह तहसील के रुड़की गांव का रहने वाला था। अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि गुरप्रीत सिंह की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है। कुंडली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल सकेगा। वह अंसल सुशांत सिटी के पास ट्रॉली में अकेला ही रह था। बुधवार सुबह उसे पास के ही नीम के पेड़ पर रस्सी से लटका हुआ पाया गया।

देश के 733 जिलों के 38 लाख से अधिक छात्र राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में भाग लेंगे

नई दिल्ली (आरएनएस)। देशभर में 733 जिलों के 1.23 लाख स्कूलों के 38 लाख से अधिक छात्र शुक्रवार को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) में भाग लेंगे। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हर तीन साल में आयोजित होने वाले इस सर्वेक्षण में छात्रों द्वारा तीसरी, पांचवीं और आठवीं कक्षा के स्तर पर विकसित दक्षताओं का आकलन किया जाता है। एनएएस पिछली बार वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था और इसे 2020 में होना था। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण सर्वेक्षण को इस साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। मंत्रालय को उम्मीद है कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 733 जिलों में लगभग 1.23 लाख स्कूल के 38 लाख से अधिक छात्र सर्वेक्षण में शामिल रहेंगे। एनएएस तीसरी और पांचवी कक्षा के लिए भाषा, गणित और ईवीएस में आयोजित किया जाएगा जबकि आठवीं कक्षा के लिए भाषा, गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान तथा 10वीं कक्षा के लिए भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में आयोजित किया जाएगा।

अब तक 5.5 करोड़ घरों में पेयजल की हुई आपूर्ति

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को कहा कि सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न सभी बाधाओं के बावजूद 5.5 करोड़ घरों को पेयजल की आपूर्ति की है। पांचवें आईएससी-फिक्की स्वच्छता पुरस्कार और भारत स्वच्छता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि कुल 8.5 करोड़ घरों में अब अब तक पेयजल की आपूर्ति की गई है। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में, केवल 17 प्रतिशत घरों में नल के पानी की सुविधा थी, लेकिन कोविड-19 की सभी बाधाओं के बावजूद हमने 27 प्रतिशत घरों में पानी उपलब्ध कराया और कुल तीन करोड़ घरों में पानी पहुंच गया। अब यह संख्या बढ़कर 8.5 करोड़ हो गई है। इस तरह अब 5.5 करोड़ घरेलू महिलाओं को पानी की समस्या से राहत मिली है।

देश की सुरक्षा से ज्यादा महत्व पर्यावरण को दिया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

» भारत-चीन सीमा विवाद का जिक्र करते हुए न्यायालय ने कही ये बात

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यह सवाल विचार योग्य है कि एक संवैधानिक कोर्ट देश की सुरक्षा को प्रभाव डालने वाले मामलों में पर्यावरण संबंधित मसलों के आधार पर कितना दखल दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या सेना की जरूरत के मुताबिक रणनीतिक बुनियादी स्ट्रक्चर के विकास के रास्ते में संवैधानिक अदालत को आना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में चार धाम परियोजना के तहत इंडिया चीन सीमा के पास सड़कों के चौड़ीकरण से संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान उक्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के इंडिया चाइना सीमा विवाद की ओर संकेत देते हुए ये बातें कही।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सवाल है कि क्या हम यह कह सकते हैं कि देश की सुरक्षा से ज्यादा तरजीह पर्यावरण को दिया जाना चाहिए? केंद्र सरकार ने अपने जवाब में सड़क परियोजना के चौड़ीकरण का कारण राष्ट्रीय सुरक्षा बताया है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि ऊंचाई पर राष्ट्रीय सुरक्षा दाव पर लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक कठिन स्थिति है अदालत के लिए क्योंकि कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर यह सब टूरिज्म के लिए हो रहा होता तो हम इस मामले में कठिन शर्त लगा सकते थे। लेकिन जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो और मामला सीमा की रक्षा से जुड़ा हुआ हो तो फिर हमारे लिए भी कठिन और गंभीर स्थिति हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ की ओर से अर्जी दाखिल कर सड़क को चौड़ा करने के लिए स्टेज वन और वाइल्ड लाइफ मंजूरी के खिलाफ अपील की गई। याचिका में कहा गया है कि इस परियोजना के कारण बड़ी संख्या में पेड़ की कटाई होगी और पर्यावरण को भारी नुकसान होगा।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सराकर ने कहा कि इस परियोजना का लाभ सुरक्षा के मद्देनजर भी है। कहा गया है कि भारत चीन सीमा पर आर्म्ड फोर्स की तैनाती में और वाहनों की आवाजाही में सहूलियत होगी। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सेना के सदस्यों को ले जाने और सामानों के ट्रांसपोर्टेशन में एक तय सीमा की चौड़ाई की सड़कों की जरूरत है। सेना के आवाजाही के लिए भी यह जरूरी है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने चार धाम परियोजना के लिए 10 मीटर की सड़क की चौड़ाई का समर्थन करने वाली हाई पावर कमिट के बहुमत के राय को मंजूर करने की गुहार लगाई थी।

केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मिनिस्ट्री ने चार धाम परियोजना के लिए 10 मीटर सड़क की चौड़ाई का समर्थन करने वाली हाई पावर कमिटी की सिफारिश का समर्थन किया है। केंद्र ने कहा कि कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिटी के 26 में से 21 मेंबरों द्वारा आर्मी के भारत चीन सीमा पर आने जाने के मद्देनजर रास्ता चौड़ा करने पर सहमति दी है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि भारत चीन सीमा पर मौजूदा जो स्थिति है, उसको देखते हुए सड़क की जो मौजूदा चौड़ाई तय है उसे 5.5 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर किया जाना चाहिए।

लगातार चौथे दिन बारिश में डूबा तमिलनाडु, आज भी संभावना

नई दिल्ली (आरएनएस)। तमिलनाडु में भारी बारिश लगातार तबाही मचा दी है। अभी मौसम विभाग का कहना है कि चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, और तिरुवनमलाई के साथ-साथ पुडुचेरी जैसे कई इलाकों में बुधवार को गरज के साथ-साथ भारी बारिश देखने को मिलेगी। राज्य में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। 9 नवंबर को सुबह से शुरू होकर रात 9.30 बजे तक कराईक्कल में लगभग 20 सेंटीमीटर और नागपट्टिनम में लगभग 15 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी तरह आज भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु में मंगलवार को भी इसी तरह की बारिश दर्ज की गई। आईएमडी के अनुसार, 24 घंटों में कराईक्कल में लगभग 20 सेंटीमीटर और नागपट्टिनम में लगभग 15 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने कहा, 11 नवंबर तक तटीय तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों के विभिन्न जिलों में अलग-अलग अत्यधिक भारी बारिश (20 सेमी) की संभावना है।

निम्न दबाव प्रणाली उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ती रहेगी और इसके 11 नवंबर को तमिलनाडु तट तक पहुंचने की संभावना है। एक और निम्न दबाव के क्षेत्र के 13 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर विकसित होने और अगले 48 घंटों में उत्तर-पश्चिम की ओर भारत की ओर बढ़ने की संभावना है।

मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, निम्न दबाव प्रणाली से बंगाल की खाड़ी में खराब स्थिति पैदा हो जाएगी और मछुआरों को 11 नवंबर तक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट से दूर बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की सलाह दी गई है। आईएमडी ने यह भी कहा है कि सिस्टम के प्रभाव में बारिश से दृश्यता कम हो सकती है, जल-जमाव के कारण ट्रैफिक जाम हो सकता है और कमजोर इमारतों को कुछ नुकसान हो सकता है।

भ्रष्टाचार के मामलों में मिजोरम के मुख्यमंत्री को मिली क्लीन चिट

आइजोल (आरएनएस)। एक विशेष अदालत ने मिजोरम के मुख्यमंत्री और मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के प्रमुख जोरमथांगा को सत्ता के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति रखने के दो मामलों में बरी कर दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के एक अधिकारी ने कहा कि विशेष अदालत के न्यायाधीश वनललेनमाविया ने अपने आदेश में कहा कि अदालत को यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले कि जोरमथांगा की संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है, इसलिए, उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। एसीबी के आरोपपत्र में दावा किया गया था कि 2003 में जोरमथांगा ने एक हलफनामे के माध्यम से घोषणा की थी कि उनके पास 54.18 लाख रुपये की संपत्ति है और 2008 के चुनावों से पहले यह बढ़कर 1.38 करोड़ रुपये से अधिक हो गई, बिना आय का कोई ज्ञात स्रोत। 2009 में, दो स्थानीय संगठनों, जिनमें पीपुल राइट टू इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटिंग सोसाइटी ऑफ मिजोरम शामिल है, जो पिछले भ्रष्टाचार-विरोधी प्रहरी है, ने जोरमथांगा के खिलाफ एंगल आयरन पोस्ट की खरीद के लिए एक लोक सेवक के रूप में सत्ता के दुरुपयोग के लिए मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने 1 और मामला दर्ज किया, 3 गिरफ्तार

» बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामला

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में एक और मामला दर्ज किया, इसके अलावा हिंसा से संबंधित एक अन्य मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। उच्च न्यायालय के 19 अगस्त के आदेश के अनुसार, जांच एजेंसी ने विश्वजीत महेश की कथित हत्या से जुड़े मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है।

यह मामला पहले 5 मई को पश्चिम मेदिनीपुर के सबांग थाने में दर्ज किया गया था। चार मई की रात महेश पर आरोपितों ने लोहे की रॉड और तलवार से हमला कर दिया था।

पीड़ित को एक तालाब में पाया गया और उसे सबांग अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सीबीआई द्वारा 1 सितंबर को दर्ज एक अन्य मामले में जांच एजेंसी ने तीन आरोपियों - मेराजुल हक, एंटाजुल इस्लाम और मोहम्मद इसराफिल अली उर्फ इप्पी को गिरफ्तार किया है।

यह मामला शुरू में 3 मई को जिला उत्तर 24 परगना के दत्तापुकुर पुलिस स्टेशन में इस आरोप में दर्ज किया गया था कि आरोपी ने पीड़ित और परिवार के सदस्यों को उसी दिन अपने खेत में काम करने के दौरान पकड़ लिया था। आगे आरोप लगाया गया था कि आरोपी उन पर आग्नेयास्त्रों, बमों और लाठी से हमला किया और हमले के दौरान पीड़ित की मौत हो गई।

गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपी थी।

इसी तरह, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी 2 मई को बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हुए कम अपराधों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।

एथेनॉल की कीमतों में हुआ इजाफा

» सरकार ने खरीद तंत्र को दी अनुमति

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल में मिलाने के लिए गन्ने से बनने वाले एथेनॉल की कीमतों में 1.47 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों पर केंद्रीय समिति ने दिसंबर 2021 से शुरू हो रहे आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल की कीमतों को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा एथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने शर्करा सत्र 2020-21 के लिए अलग-अलग कच्चे माल से बनने वाले एथेनॉल की कीमतों को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके तहत सी हैवी शीरे से बनने वाले एथेनॉल की कीमत 45.69 से बढ़ाकर 46.66 रुपये प्रति लीटर और बी हैवी से बनने वाले एथेनॉल की कीमत 57.61 से बढ़ाकर 59.08 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं, गन्ने के रस, चीनी/चीनी सिरप से बनने वाले एथेनॉल की कीमत 62.65 रुपये से बढ़ाकर 63.45 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। ठाकुर ने कहा कि भारत की योजना साल 2025 तक पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाकर 20 फीसदी करने का लक्ष्य है। पेट्रोल में एथेनॉल की अधिक मात्रा मिलाने से भारत को अपने तेल आयात बिल में कटौती करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से गन्ना किसानों और चीनी मिलों को भी काफी लाभ पहुंचेगा।

जूट के थैलों में होगी अब खाद्यान्न की पैकिंग - इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने जूट पैकेजिंग मैटेरियल अधिनियम, 1987 के तहत जूट वर्ष 2021-22 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्रियों के लिए आरक्षण मानकों को अनुमति भी प्रदान कर दी। केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने बताया कि यह अनुमति मिलने के बाद 100 फीसदी अनाज और 20 फीसदी चीनी की पैकिंग जूट के थैलों में ही की जाएगी।

योगी आदित्यनाथ ने किया साधु संतों के साथ भोजन

मथुरा (आरएनएस)। उत्तरप्रदेश के मथुरा में ब्रजरज उत्सव का उद्घाटन कराने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कार्यक्रम के तहत ब्रज के साधुसंतों के साथ पंगत में बैठकर भोजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन स्थित टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेंटर पर पहुंचकर साधु संतों का अभिनंदन किया। प्रसाद ग्रहण करते हुए योगी आदित्यनाथ ने साथ बैठे हुए साधु संतों से उनका हाल-चाल भी जाना। मुख्यमंत्री और साधु-संतों के लिए मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन, खीर, बूंदी के लड्डू, मोहनथार, पूड़ी, कचौड़ी, रायता, चटनी, काशीफ्ल की सब्जी, आलू कचौड़ी, सब्जी एवं गोभी आलू की सब्जी तैयार की गई। इस दौरान प्रमुखरूप से महंत हरिशंकर दास नागा, महंत फेलडोल बिहारी दास, महंत सुंदरदास, संत मदनमोहन दास, महंत लाडली शरण दास सहित ब्रज के अनेक साधु संत मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बडी संख्या में लोग पहुंचे। गोवर्धन क्षेत्र भाजपा नेता और कार्यकर्ता राधाकुंड आन्यौर और आस पास के गांव के लोग बस द्वारा मथुरा वृंदावन के लिए पहुंचे।

एपीडा ने किसानों के लिए 75 जागरूकता-व-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुगंधित और लंबे दानों वाले बासमती चावल के गुणवत्ता उत्पादन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के सहयोगी बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन (बीईडीएफ) ने अच्छी कृषि संबंधी प्रथाओं के अनुपालन के लिए उगाए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में बासमती चावल की खेती से जुड़े किसानों को संवेदनशील बनाने के लिए अभिनव कदम उठाये हैं।

पहलों के हिस्सों के रूप में, बीईडीएफ ने सात राज्यों में उच्च गुणवत्तापूर्ण बासमती चावल उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा दिल्ली के चावल निर्यातक संघों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्य कृषि विभागों के सहयोग से 75 जागरूकता-व-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। बीईडीएफ बासमती चावल उगाने वाले राज्यों विभिन्न एफपीओ, निर्यातक संघों आदि के लिए तकनीकी साझीदार के रूप में भी जुड़ा है।

बीईडीएफ ने 'आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों' के हिस्से के रूप में, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जहांगीरपुर गांव से 16 जुलाई, 2021 को जागरूकता-व-प्रशिक्षण कार्यशाला लॉन्च किया, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर को मनाने तथा समारोह आयोजित करने की भारत सरकार की एक पहल है। जागरूकता अभियानों का आयोजन 'कीटनाशकों का विवेकपूर्ण उपयोग तथा अच्छी कृषि संबंधी प्रथाओं के अनुपालन' की थीमों पर फोकस करते हुए किसानों के लिए किया गया था। जागरूकता अभियानों का एक अन्य उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता के बीजों की गैर-उपलब्धता के मुद्दे का समाधान करने के लिए बीज उत्पादन करने हेतु किसानों को प्रशिक्षित करना था।

कार्यशाला में, किसानों को कीट-कीड़ों और बासमती चावल के रोगों की पहचान करने तथा उनके प्रबंधन की विभिन्न पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। 2021 के पूरे बासमती उगाए जाने वाले सीजन में जागरूकता अभियानों के दौरान बासमती चावल के निर्यात में समस्याएं तथा चावल उद्योग की अपेक्षाओं जैसे मुद्दों को उत्पादकों एवं निर्यातकों के संज्ञान में लाया गया।

एपीडा को गंगा के मैदानी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बासमती चावल के एकमात्र संरक्षक के रूप में भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दिया गया है। फरवरी, 2016 में जारी जीआई प्रमाणन के तहत, सात राज्यों- पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली तथा जम्मू एवं कश्मीर के 77 जिलों को बासमती चावल उगाये जाने वाले क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है।

बीईडीएफ द्वारा आयोजित जागरूकता अभियान के दौरान, वैज्ञानिकों ने किसानों तथा निर्यातकों को स्थानीय भाषाओं में बासमती चावल के निर्यात में कीटनाशक अवशेष समस्या तथा नर्सरी पालन, समेकित पोषण और जल प्रबंधन सहित उत्पादन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के बारे में विस्तार से बताया। कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा अच्छी कृषि संबंधी प्रथाओं के अनुपालन के बारे में जानने के लिए कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसान, निर्यातक, एफपीओ आदि एकत्रित हुए जिनका आयोजन सात राज्यों में 75 विभिन्न स्थानों पर किया गया।

पंजाब में, 25 जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जबकि उत्तर प्रदेश में 21, हरियाणा में 17, उत्तराखंड में 05, जम्मू एवं कश्मीर में 03 तथा हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली में दो-दो जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रमों के आयोजन के जरिये, किसानों को जानकारी दी गई कि बासमती चावल की खेती एक भारतीय परंपरा है और यह सामूहिक उत्तरदायित्व है कि इस परंपरा को बनाये रखा जाए क्योंकि वैश्विक बाजार में चावल की भारी मांग है।